

विधि बैंक प्रकरण संख्या 79/2018(GCMS : 2018/00149) आईडीबीआई बैंक लि.
शाखा श्रीगंगानगर बनाम 1. दीपक अग्रवाल निवासी ई-5 आनंद विहार, गार्ड नं. 34,
श्रीगंगानगर -335001 राजस्थान

25.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए।
प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने आज
कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। पत्रावली का अवलोकन किया गया।



प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय
आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002
की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी दीपक अग्रवाल
को ऋण सुविधा के रूप में 18.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये अठारह लाख मात्र)
का ऋण दिनांक 05.04.2014 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में
अप्रार्थी दीपक अग्रवाल द्वारा अपनी चल सम्पत्ति TOYOTA INNOVA CRYSTA ZX-
AT, Reg. No. RJ-13-C1-Temp-1487, Engine No. 1GDA001491, Chassis No.
MBJAA3EM600750123-0416 प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है
कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं
किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 04.07.2017 को अनर्जक
परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम
दिनांक 06.12.2017 को 16,95,878/- रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व
अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60
दिवस का नोटिस दिनांक 28.12.2017 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए
जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड
डाक से भिजवाये गये है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त
बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी दीपक अग्रवाल द्वारा
सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति TOYOTA INNOVA

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

CRYSTA ZX-AT, Reg. No. RJ-13-C1-Temp-1487, Engine No. 1GDA001491, Chassis No. MBJAA3EM600750123-0416 का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी दीपक अग्रवाल को 18.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये अठारह लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 05.04.2014 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी दीपक अग्रवाल द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति TOYOTA INNOVA CRYSTA ZX-AT, Reg. No. RJ-13-C1-Temp-1487, Engine No. 1GDA001491, Chassis No. MBJAA3EM600750123-0416 प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.07.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 28.12.2017 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 02.01.2018 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानन्द

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी दीपक अग्रवाल की दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति TOYOTA INNOVA CRYSTA ZX-AT, Reg. No. RJ-13-C1-Temp-1487, Engine No. 1GDA001491, Chassis No. MBJAA3EM600750123-0416 जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 28.12.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 28.12.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थी दीपक अग्रवाल को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 02.01.2018 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक/प्राप्ति रसीद की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के प्राप्ति रसीद की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अनुसार अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस की तामील उस स्वयं पर या उसके द्वारा नियुक्त एजेंट पर होनी आवश्यक है और अप्रार्थी नोटिस की तामील से बचने का प्रयास करते है तो नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है।

नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर

Demand Notice

(1) The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmitting at the place where the borrower or his agent empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that **the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper, one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.**

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the branches of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other **notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.**

(4) Where there are more than one borrower the demand notice shall be served on each borrower.

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 28.12.2017 को रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गये हैं में धारा 13(2) के नोटिस की तामील अप्रार्थी को नहीं हुई है, जो उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 के RULE 3 के तहत मान्य नहीं है।** इस प्रकार बैंक द्वारा ऋणी को तामील

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो की अवहेलना की है। इसलिए ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील होना नहीं माना जा सकता।

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड ने 2012 Cr. I.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versus Arvind Kumar & Anr के पैरा-13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

13. In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that generally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see also : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and Karnataka State Road Transport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.डी.बी.आई. का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 का स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुकमणि रियार सिद्दीग) .
जिला मजिस्ट्रेट
ब्रिजवा मिनरे
श्री गंगानगर